

पत्रांक - बी1-3- 65 /2018- 2191
प्रेषक

पटना, दिनांक - 15 मई, 2018 ई०।

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

विषय :- मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण के संबंध में।

प्रसंग:- भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 दिनांक 07.05.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-2087 दिनांक 09.05.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र पत्रांक 2087 दिनांक 09.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) के कड़िका-7 Rationalization of Polling Stations and Formation of Sections का संदर्भ किया जाये। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण दिनांक 31.08.2018 (शुक्रवार) तक पूर्ण कर लिया जाना है, तत्पश्चात् अर्हता तिथि 01.01.2019 के आधार पर प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन दिनांक 01.09.2018 (शनिवार) को होना निर्धारित है।

भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र में स्पष्ट निदेश है कि सभी मतदान केन्द्रों पर चुनाव हेतु VVPATs का उपयोग होगा, जिसके कारण किसी भी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर अधिकतम 1200 निर्वाचक और शहरी क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर अधिकतम 1400 निर्वाचक ही सम्बद्ध किये जायेंगे।

मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत Manual on Polling Stations, January 2016 में दिये गये निर्देश के आलोक में किये जाना है। भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट <http://eci.nic.in> पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस पत्र के साथ Manual on Polling Stations, January 2016 के अध्याय-4 Rationalization/Modification in The List of existing Polling Stations की छायाप्रति संलग्न है।

आयोग के उक्त निदेश के आलोक में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण से लेकर प्रारूप निर्वाचक सूची की तैयारी किये जाने वाले कार्यों का विषयवार समय सीमा निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

A) Pre Rationalization Activity

1. 100% Physical verification of Polling Station	- 01 June 2018 (Friday) to 15 June 2018 (Friday)
2. Preparation of Draft list of Polling Station	- 16 June 2018 (Saturday) to 26 June 2018(Tuesday)

B) Rationalization Activity

1. Publication of draft list of Polling Stations & 1 st Meeting with representatives of recognized Political Parties, MPs and MLAs	- 27 June 2018 (Wednesday)
2. Period for filing Claims and Objections	- 28 June 2018 (Thursday) to 07 July 2018 (Saturday)
3. Disposal of Claims and Objections	- Before 15 July 2018 (Sunday)
4. Meeting with representative of recognized Political Parties, MPs and MLAs	- 16 July 2018 (Monday) to 20 July 2018 (Friday)
5. Proposal of Polling Stations to be sent to CEO Office, Bihar	- 21 July 2018 (Saturday) to 25 July 2018 (Wednesday)
6. Proposal to be sent to ECI for approval	- 26 July 2018 (Thursday) to 31 July 2018 (Tuesday)

7. Approval form ECI	- Before 07 August 2018 (Tuesday)
8. Preparation of co-relation table and updation of Control Table	- Before 15 August 2018 (Wednesday)
9. Preparation of supplements, integration and preparation of Draft Electoral Roll	- up to 31 August 2018 (Friday)

मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया –

- मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन (Physical verification of Polling Station)** – मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम शत-प्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन Manual on Polling Stations, January 2016 के अध्याय-4 शीर्षक Rationalization /Modification in The List of existing Polling Stations की कड़िका-4.3.1 (iii) में दिये गये निर्देश के आलोक में किये जाने हैं। मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन संलग्न प्रपत्र में दिनांक 01 जून 2018 (शुक्रवार) से 15 जून 2018 (शुक्रवार) तक पूर्ण कर लिया जाना है।

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट पर निर्धारित मॉड्यूल (Module) में प्रविष्ट किया जाना है जिसके लिए ऑन-लाईन प्रविष्टि हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रविष्टि का कार्य दैनिक आधार पर प्रतिदिन किया जाना है, जिससे कार्य की प्रगति की समीक्षा हो सके।

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं निर्वाचकों के मानक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होगा कि कितने मूल मतदान केन्द्र में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके अनुसार मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची में प्रस्ताव सम्मिलित किया जाना है।
- निर्वाचकों की अधिकतम संख्या के आधार पर मतदान केन्द्रों का निर्माण** – भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार किसी भी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर अधिकतम 1200 निर्वाचक और शहरी क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर अधिकतम 1400 निर्वाचक से अधिक निर्वाचक सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 दिनांक 07.05.2018 में स्पष्ट किया गया है कि मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने (Maintain) के लिए सर्वप्रथम आस-पास के मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानान्तरण किया जाना है। निर्वाचकों का स्थानान्तरण पूर्ण परिवार के निर्वाचकों का एक साथ होना है। यदि मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या बनाए रखने के लिए युक्तिकरण के शर्तों के अनुरूप मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानान्तरण नियमानुकूल नहीं है तो वैसी परिस्थिति में नये मतदान केन्द्र की स्थापना आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण हेतु दिये गये निदेश के आलोक में किया जाना है।
- मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची की तैयारी (Preparation of Draft list of Polling Station)** – मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची की तैयारी का कार्य 26 जून 2018 के पूर्व पूर्ण कर लिया जाना है। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के आधार पर मूल मतदान केन्द्रों में संशोधन प्रस्ताव एवं मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा को बनाए रखने के लिए प्रस्तावित मतदान केन्द्रों को मिलाकर Manual on Polling Stations, January 2016 के Annexure-I (छायाप्रति संलग्न) में मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची तैयार की जानी है।
- मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों संबंधित विधायक और सांसद के साथ प्रथम बैठक** – दिनांक 27 जून 2018 को विहित प्रपत्र (Annexure-1) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जाना है। दिनांक 27 जून 2018 को ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, विधायक, सांसदों के साथ बैठक कर उन्हें मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची की प्रति उपलब्ध कराना है एवं उनसे निर्धारित अवधि 07 जुलाई 2018 तक दावा एवं आपत्ति देने का अनुरोध किया जाना है।
- दावा एवं आपत्ति प्राप्त करना** – दिनांक 28 जून 2018 से 07 जुलाई 2018 तक मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जाना है।

6. दावा एवं आपत्ति का निस्तार – प्राप्त दावा एवं आपत्ति का निस्तार संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा ससमय कराया जाना है। प्रत्येक दावा एवं आपत्ति पर किये गये जाँच एवं निष्कर्ष का अभिलेख संधारित करना है।
7. राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों संबंधित विधायक एवं सांसदों के साथ बैठक – मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची पर प्राप्त दावा एवं आपत्ति के निस्पादन का फलाफल से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों संबंधित विधायक एवं सांसदों को अवगत कराना है।
8. मतदान केन्द्रों का प्रारूप सूची में आवश्यक संशोधन एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार कार्यालय को मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव भेजना – जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, संबंधित विधायक एवं सांसदों के साथ बैठक के उपरान्त प्रारूप मतदान केन्द्रों की सूची दावा एवं आपत्ति निस्तार के फलाफल को अंकित करते हुए विहित प्रपत्र (Annexure-I) में प्रतिवेदन, Scrutiny sheet for list of Polling Stations (Annexure-II), Certificate to be furnished along with List of Polling Stations (Annexure-III), राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों संबंधित विधायकों एवं सांसदों की द्वितीय बैठक की कार्यवाही की प्रति एवं विधान सभावार नक्शा के साथ संबंधित जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में उपस्थित होंगे। जिलों से प्रस्ताव प्राप्त करने संबंधित समय सारणी बाद में संसूचित किया जायेगा।
9. आयोग का अनुमोदन एवं अनुमोदित मतदान केन्द्रों अन्तिम प्रकाशन – भारत निर्वाचन आयोग से मतदान केन्द्रों का अनुमोदन प्राप्त होने पर जिला स्तर पर इसका अन्तिम प्रकाशन किया जाना है।
10. Preparation of co-relation table and Updation of control table – अनुमोदित मतदान केन्द्र की सूची के आधार पर जिला स्तर पर निर्वाचकों से संबंधित co-relation table तैयार करना है एवं इसके आधार पर control table को update करना है।
11. Preparation of supplements integration and preparation of draft electoral roll – उक्त संशोधनों को शामिल करते हुए प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जाना होगा।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

13.5.2018
(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक –बी1-3- 65/2018- 2191

पटना, दिनांक –15 मई, 2018 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य/सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

13.5.2018
(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक –बी1-3- 65/2018- 2191

पटना, दिनांक –15 मई, 2018 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

13.5.2018
(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक - बी1-3- 65 /2018- 219/

पटना, दिनांक - 15 मई, 2018 ई0।

प्रतिलिपि :- श्री संजीव शंकर, एस.एल.ए. निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन हेतु संलग्न विहित प्रपत्र के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त पत्र की कंडिका-1 में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट पर मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का विहित प्रपत्र के अनुसार निर्धारित मॉड्यूल तैयार कर अविलम्ब सूचित करने की कृपा की जाये।

अनु0:- यथा उपर्युक्त।

13.5.2018

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

14

478/CEO
7/5/18

By e-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018

Dated: 7th May, 2018

Dy. CEO (VMS)

7/5/18

Dy. CEO (P&K)

The Chief Electoral Officers of All States and Union Territories.

(Except Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan)

Subject: Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature w.r.t. 01.01.2019 as qualifying date - Programme - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that as per existing policy, revision of electoral rolls with reference to 1st January of the coming year as the qualifying date is done in later part of each year in all States/UTs (normally in the last quarter of a year) so that final publication of the electoral rolls could be made in the first week of January of the succeeding year. The revision schedule is prepared in such a manner that the electoral rolls are finally published much before National Voters' Day (25th January of every year) so that EPICs generated for new electors especially young voters (18-19 years) can be distributed to them in ceremonial manner on the day of NVD. The Commission, taking all aspects into consideration especially the impending general election to the Lok Sabha, 2019, has directed to undertake Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature w.r.t. 01.01.2019 as qualifying date in all the States/UTs (except Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan) as per the schedule below:-

42191491-2
9-5-18

Sl. No.	Activities	Period
1.	Pre-revision Activities Preparation of publicity/training material and Cascaded training of Officers	Before 11 th May 2018 (Friday)
2.	House to House Field verification by BDOs	12 th May 2018 (Tuesday)

		June 2018 (Wednesday)
3.	Rationalization of Polling Stations and of PS Buildings	Physical verification 21 st June 2018 (Thursday) to 31 st July 2018 (Tuesday)
4.	Updation of Control Tables, Preparation of supplements, integration and preparation of draft electoral roll	01 st August 2018 (Wednesday) to 31 st August 2018 (Friday)
5.	Revision Activities Publication of Integrated draft electoral roll	1 st September 2018 (Saturday)
6.	Period for filing claims & objections	1 st September 2018 (Saturday) to 31 st October 2018 (Wednesday)
7.	Disposal of claims and objections	Before 30 th November 2018 (Friday)
8.	Updating database and printing of supplement	Before 3 rd January 2019 (Thursday)
9.	Final publication of electoral roll	4 th January 2019 (Friday)

2. The Commission has decided that the revision shall be a Special Summary Revision of intensive nature and be undertaken as per the above schedule, in accordance with provisions contained in Manual on Electoral Roll, 2016, along with subsequent relevant instructions.

3. In the constituencies where bye election has been announced on 26th April 2018, the above said revision shall not be taken for the time being, however, continuous updating will remain continue till the prescribed period i.e. till the last date of making nominations. Chief Electoral Officer, immediately after completion of bye-election, shall propose a separate schedule to the Commission for the above-said activities of Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 01.01.2019 as the qualifying date in the said constituencies.

4. The CEOs shall go through the schedule and if any minor change in the above schedule is required, a request should be made with full justification to the Secretary/Pt. Secretary in charge of the concerned territorial division in the Commission, for the Commission's approval within seven days from the date of issue of this letter. No change in the schedule approved by the Commission will be permitted, thereafter.

5. Pre-revision activities:- (i) As the revision of electoral rolls actually starts with draft publication of electoral rolls, various pre-revision activities are required to be completed well before the actual commencement of Revision of Electoral Rolls, with the sole intention of achieving high fidelity electoral rolls. Accordingly, pre-revision activities, like Training and Orientation of EROs/AEROs, Appointment of Booth Level Officers (BLOs) and their Training and Orientation, Identification of critical gaps/deviations in electoral rolls and strategy to bridge/remove the same, deletion of identified repeat/multiple entries/Demographically Similar Entries/dead electors entries after service of due notice, Rationalization of Polling Stations (including standardization and mapping of polling stations), determination of parts/section boundaries, optimization of sections and preparation of improved digital maps of polling areas) along with 100% physical verification of Polling stations, Preparation of CEO's website for draft publication of integrated rolls and providing search facility, Standardization of search facility at website, updating of Control Tables (including polling stations updating) and database and integration of rolls and detailed SVEEP Campaign etc., shall be planned by the States/UTs and accomplished in time-bound manner as per the given schedule so as to ensure their successful completion before draft publication of electoral rolls. A detailed report on completion of pre-revision activities shall be sent by the Chief Electoral Officer to the Territorial Secretary/Pr. Secretary in charge.

(ii) It is further clarified that all the Forms received during continuous updating period shall be disposed of and registered death cases be removed from the roll after following due procedure. The supplements shall be prepared well before the draft publication of electoral rolls, 2019 and shared with political parties and kept in record without its publication, so that outcome of disposal of such Forms are taken into account in integrated draft electoral roll at the time of its publication.

6. House to House Field Verification: (i) For field verification, the BLOs will be given a pre-filled BLO register containing the details of existing electors in their respective part for H2H field visit and to get the said details verified from the head of the family. In addition to that, BLOs will collect the following information

- a) Un-enrolled eligible citizens (eligible on 01.01.2018)
- b) Prospective voters (eligible on 01.01.2019)
- c) Multiple entries/dead electors/Permanently Shifted Electors
- d) Correction in the ER entries

(ii) On completion of field verification, each BLO and each ERO shall furnish the certificate to the Chief Electoral Officer through DEO concerned, to the effect that details in respect of all the four items have been collected 100% without any left over.

7. **Rationalization of Polling Stations and Formation of sections:** (i) As the Commission has decided to use WPAT in all the future elections, no relaxation/deviation will be allowed in the upper limit of 1200 and 1400 electors in rural and urban polling stations respectively. The Commission has, therefore, directed all the polling stations with electors beyond the said upper limit will invariably be rationalized/modified as per the given schedule and before the draft publication of electoral rolls in accordance with instructions contained in Manual on Polling Station, 2016. A new Polling Station shall be created only after rationalizing the sections to the adjacent Polling Stations to the possible extent. Proposal on change of location shall be sent to the Commission only after 100 % physical verification/inspection of the Polling Stations and along with its longitude and latitude. Latitude and Longitude of all Polling Stations, newly identified and proposed for creation/change of location of Polling Stations shall be captured and details of the same shall be updated in the ERO-Net Dashboard. (ii) Other objectives of rationalization of polling stations are to group all the family members and neighbors in a section and maintain uniformity of addresses in ER and EPICs.

(iii) For proper formation of Sections the following units may be formed :-

- a) Nuclear/immediate family (Husband, Wife and eligible children)
- b) Joint Family/Household (Group of several nuclear families related to each other and living at the same place)
- c) Door/Patal No.
- d) Building/Block/Tower consisting of a no. of doors/flats.
- e) Street

(iv) Each of the above units may be given notional number and also their permanent number, if given by Civic Bodies, be captured by the BLOs, during House to House verification.

(v) While creating a new polling station or re-organizing the existing polling stations by creating/merging/ attaching sections to the adjacent polling stations, the fulfillment of following conditions should be ensured:

(a) No family is broken and all the family members are kept in the same section and at the same place.

(b) Electors residing in a building are enrolled in the same part,

(c) As far as possible electors residing in a Street are enrolled in the same part, and

(d) The electors of so merged/attached polling station are not required to travel for more than two Kilometer distance and to cross any natural barriers.

(vi) For rationalization and re-organization of the existing polling stations, an application is being developed by CDAC and in due course desktop version and Mobile App version will be made available on ERO Net for guidance of EROs/DEOs, which they can use, if required, or else CEOs may decide for manual rationalization.

8. **Preparation of Formats 1-8:** The electors' information in prescribed Formats 1-8 related to draft publication of the electoral roll shall be furnished by the CEO along with his studied comments and explanatory memoranda to the Commission well before draft publication. Every DEO/ERO will do the similar study for his/her District/Assembly Constituency and forward the same to the CEO and also keep this ready for reference by Roll Observer/CEO. CEOs shall adopt the same methodology for estimation of projected 18+ populations (age cohort wise) on 01.01.2019 as prescribed by the Commission. The State/UT, who is at variance with the methodology, as suggested by the Commission, may use their own methodology; if they feel that it is more scientific and realistic in context of the concerned State and in such case CEO has to mention about the rationale behind keeping existing methodology in the Format 1-8.

9. **Display of list of claims and objections-** As per rule 16 of the Registration of Electors Rules, 1960, ERO shall prepare lists of claims and objections in form 9,10,11 and 11A and exhibit one copy of such lists on a notice board in the his office. Besides, list of all claims and objections received should be put up on the website of CEO so that citizens are able to see the list and lodge objections with the concerned ERO. In addition to this

- (i) Adequate publicity should be given by CEO to the fact that list of claims and objections is available on his/her website and objections can be raised before the EROs based on this list.
- (ii) CEO, all DEOs and all EROs should hold meetings with political parties and inform them about the publication of list of claims and objections on CEO's website and the latest instructions of the Commission about disposal of claims and objections.
- (iii) Political parties should be informed in writing by the CEO/DEO/ERO about publication of list of claims and objections on CEO's website
- (iv) List of claims and objections should be made available by ERO to all political parties on weekly basis. For this purpose the ERO should call a meeting of all political parties.

regular interval and personally handover list of claims and objections to them and obtain acknowledgment. It is to be added that the list should be incremental instead of cumulative.

10. Decisions on Claims and Objections - Decision on claims and objections should be taken only after all of the following conditions are complied -

- (i) At least seven clear days' period has passed after list of claims and objections has been published on all of the following -
 - a) Website of CEO, as clickable lists for each polling station
 - b) Notice board of ERO (In Forms 9, 10, 11 and 11 A of RERs 1960)
 - c) Notice board of polling station (In Forms 9, 10, 11 and 11 A of RERs 1960)
 - d) A personal notice has been served on the person whose name is proposed to be deleted in cases other than death cases.
- (ii) At least period of seven clear days has passed after furnishing the list of claims and objections to political parties.

11. Procedure of Deletion:

11.1 Removal of Repeat/Multiple Entries/Demographically Similar Entries (DSEs):-

(i) **Repeat/Multiple Entries:** In cases of repeated / multiple entries reported by individual citizens, B.L.As of political parties and RWA representatives, the field verification must be done in each and every case. Checklist shall be generated and printed and given to concerned B.L.Os for field verification. Name of the elector should be retained in electoral roll only at the place where he is found to be ordinarily residing.

(ii) **Demographically Similar Entries (DSEs):** (a) DSEs are thrown by software, on the basis of electors' demographic details such as name, relation type, relation name, gender, DOB, age (exact/plus/minus 1 year).

(b) The ERO shall login and do table top verification on his computer monitor through image comparison of each of the probable DSEs. He shall sort out such entries and put them into 3 buckets: 'match/positive', 'not match/negative' and 'doubtful'.

(c) In respect of probable DSEs where more than one ERO are involved, all the concerned EROs will be able to see the entries relating to their AC as well as the entries repeating in other ACs and if

EROs in consultation with each other have to decide as to in which bucket the said DSE should be kept.

(d) The 'not match/negative' entries shall be flagged in the database/UNPER and in future, they will no longer be treated as DSE. For the 'match/positive' and 'doubtful' cases field verification shall be done through BLO checklist and, necessary action will be taken by ERO.

(iii) In the cases of 'verified positive DSEs and Multiple Entries, found after BLO field verification through checklists, name of the elector shall be deleted from where he is not residing after obtaining Form 7 from him. The reference number of such Form-7 shall be entered into ERO-Net. If the concerned elector refuses to submit Form 7, ERO will take necessary action for deletion of his name after following due procedure of serving notice for proposed deletion.

(iv) Deletion process of DSEs/Multiple Entries involving more than one ERO

- a) If the probable DSEs/Multiple Entries relate to 'within part' or 'within AC', necessary action shall be taken by the concerned ERO.
- b) In case of probable DSEs/Multiple Entries relate to across AC in a district, DEO concerned shall coordinate with all EROs of the constituency involved.
- c) Concerned DEOs shall supervise the exercise of de-duplication if the probable DSEs/Multiple Entries relate to AC across districts.
- d) Similarly, in case of probable DSEs/Multiple Entries relating to ACs across states CEOs of concerned states shall have to coordinate.
- e) In event of difference of opinion between/among the EROs, field verification should invariably be done by each ERO and further action for deletion taken accordingly.
- f) There may be a chance when the BLOs of different ACs may report about finding the said person ordinary residing at the given address in his part. In such case personal hearing must be fixed by the EROs to ascertain his actual place of ordinary residence.

11.2 Removal of permanently shifted Electors:

- (i) In the cases where the elector has shifted and the Booth Level Officer has been able to trace the shifted voter, a notice should be served upon the elector. Form 7 may be obtained from the elector for deletion of his name from the previous place.
- (ii) If the Booth Level Officer is not able to trace the shifted elector, the notice should be pasted at the address of the elector available in the electoral database in presence of two adult witnesses, one from the family of the shifted elector and one from the immediate neighbourhood of the

(7)

family member of the elector is available, then, witness of two persons residing in the immediate neighborhood be taken. Deletion may be done after expiry of the notice period.

- (iii) The Commission has directed that in case of mass permanent shifting, notice of proposed deletion of names of electors, who are no longer ordinary residents in that locality due to their mass shifting to another unknown places, shall be given in a local daily newspaper. Action for deletion of such names should be taken only after expiry of 7 days from the date of publication of notice in the said local daily and on the basis of response on notice, if any, received from persons concerned.

11.3. Removal of Deceased Electors:

In cases of deceased electors, Electoral Registration Officer can make deletion on the basis of death certificate from a competent authority (Registrar of Births & Deaths, Local Bodies, Sarpanch, Ward Member etc.) or Form 7 from immediate relatives/immediate neighbours/friends of the elector concerned after a field verification through B.L.O. or a report duly prepared by the Booth Level Officer with statements of at least two persons residing in the locality. In cases of dead electors, reported by BLAs/Political Parties/RWAs or other Indian citizens, field verification must be done and due procedure must be followed of issuing notice for removal of such entry.

11.4. Safeguards against wrongful deletion of names from Electoral Rolls:

- (i) Electoral Registration Officer must take special care for deletion of names of EPIC holders. If an elector has multiple EPICs, all EPICs relating to the entries which have been deleted should be taken back from him and proper record of the same should be maintained.
- (ii) Intimation about the deletion should be sent to the elector concerned through post or SMS / e-mail, in case mobile number/e-mail ID is available in the electoral database.
- (iii) In addition to the above, the Electoral Registration Officer shall prepare part wise list of names proposed to be deleted from the electoral roll in any of the above grounds and display the same in his office for a period of at least 7 days from the date of posting of the list. The said list shall be put on Chief Electoral Officer's website for public information and calling objections, if any. The said list also should be shared with recognized political parties.
- (iv) After making deletions, the final deletion list should also be furnished to recognized political parties.

- (v) The ERO shall maintain a daily monitoring register of all deletions made by him or his AEROs in the constituency during the period of continuous updation.
- (vi) The District Election Officers shall monitor the process of deletions made by the Electoral Registration Officers in the assembly constituencies comprised within the districts under their jurisdiction. The Electoral Registration Officers shall do periodic reporting of progress of revision on ERO-Net dashboard. The District Election Officers shall verify the report made by all Electoral Registration Officers in his district. The Chief Electoral Officer shall keep a close watch on the deletions made by the Electoral Registration Officers in the state by visiting and verifying ERO-Net regularly.
- (vii) In all the deletion cases where field verification is must, checklists shall invariably be generated and given to BLOs concerned for field verification and notice for proposed deletion be served in all cases except for registered death cases. For registered death cases, there is no need to issue any notice and outcome of field verification of checklist by BLO together with death certificate will suffice to delete the names of such deceased person from the electoral roll.

11.5 Mandatory verification before deletion of names from electoral rolls:

All deletions except those done on the ground of death should be verified by an officer not below the rank of Tehsildar before final order is passed on Form 7.

- ii. All cases of deletions must be cross verified personally by Electoral Registration Officer if they fall in any of the following categories: -
 - a) Deletions in polling stations where the number of deletions exceed 2% of the total electors in the voters' list of the polling stations.
 - b) Deletions where the same person is the objector in more than 5 cases.
- iii. Cases of deletions other than those made on the ground of death should be cross verified by supervisory officers in the following manner:-
 - (1) 2 % verification by Deputy DEO or equivalent officer.
 - (2) 1 % verification by DEO.
 - (3) 0.5 % verification by Roll Observer

(5)

12. Flagging of marked electors viz. MP/MLA/MLC, holders of declared offices and personalities from fields of arts, culture, journalism, sports, members of judiciary and public services etc.:

Electoral Registration Officers shall ensure that the names of all Members of Parliament and the State Legislatures, holders of declared offices, personalities from fields of arts, culture, journalism, sports, members of judiciary and public services are there in the proposed draft electoral roll. To avoid wrongful deletions of the names of such electors in future appropriate flagging should be done in the electoral database.

13. Flagging of Persons with Disabilities (PwDs) in Electoral Database: As Form-6 for enrolment in electoral roll has an optional field for giving information about disabilities, the Commission has directed that all the cases of PwDs electors who have given such information in Form 6 should be flagged in the electoral database along with category of disability so that such electors can be provided necessary facilities at the polling station at the time of poll. It is made amply clear that such information of disability should not be reflected in electoral roll in any way. As the theme of this year is "Accessible Election", Chief Electoral Officer concerned should rope in the concerned department in the State dealing with persons with disabilities to get their assistance in mapping Persons with Disabilities. Chief Electoral Officer, if he feels it necessary, can utilize services of BLOs during H2H visits for collection of such data of PwDs from electors, who are willing to disclose their disabilities. Weekly progress report in this regard may be sent to Secretary/Principal Secretary in charge of the State to review the weekly progress.

14. Supervision and Checks: - (i) As already mentioned above, for the purpose of improving health of electoral roll, the Election Commission has emphasized the need of field verification by the Booth Level Officers. As per the normal practice being followed, the Electoral Registration Officer, after digitization of claims & objections received by him, deposes Booth Level Officer concerned to make field verification in connection with the claim or objection. The Booth Level Officer after on spot verification submits his report to the Electoral Registration Officer.

(ii) There is a mechanism for supervision and check for enforcing strict accountability of the work performed by the Booth Level Officers. The Supervisor who normally has 10 Booth Level Officers under his charge shall verify 5% of each of the Booth Level Officer's verification work under him.

(iii) Above the Supervisors, each Assistant Electoral Registration Officer should verify 1% of the BLO's verification work, randomly selected from different parts under him. Assistant Electoral

Registration Officer shall field check households with more than 10 electors; abnormal gender ratio, and the first 20 polling stations with highest number of additions or deletions, under his charge.

(iv) Electoral Registration Officer shall test check the quality of disposal of claims & objections by his Assistant Electoral Registration Officers. He shall check 10% of the Forms disposed by Assistant Electoral Registration Officers. Field verification should be carried out where felt necessary. Electoral Registration Officer shall hold regular monitoring meetings with Assistant Electoral Registration Officers, Supervisors and Booth Level Officers and ensure that the work is not being done in perfunctory manner. Delinquent officials should be taken to task and corrective measures taken swiftly because ultimately the accountability stops with Electoral Registration Officer and the Electoral Registration Officer is responsible for delivering an error free roll.

(iv) Every District Election Officer is also required to be actively involved in the revision exercise. District Election Officer should hold at least a meeting every fortnight and undertake 2% checking of each of the Electoral Registration Officer's disposal of claims & objections.

(vi) The Chief Electoral Officer may also designate his own team or request the Election Commission to depute team for further state level checks as felt necessary. Ultimately it is for Chief Electoral Officer to seek the Election Commission's approval to publishing of rolls and for this the Chief Electoral Officer shall give a detailed report on state wide health check of the rolls in the prescribed formats-(Format 1-8), deviations noticed, remedial action taken etc. The Chief Electoral Officer shall also furnish an account of the checks maintained and supervision undertaken during the roll revision process and give a certificate on his/her satisfaction on the quality of roll.

(vii) Assistant Electoral Registration Officer should separately field check 1% of the additions and deletions, giving focus on such part of electoral rolls where proposed addition of electors is 4% over previous electoral roll. Both, accepted as well as rejected cases, should also be checked in those cases.

15. Monitoring: EROs/ DEOs shall do periodic reporting of progress made during the revision process on ERO-Net Dashboard. The CEO shall monitor and verify the reporting made by EROs/DEOs. It is reiterated for absolute compliance by all the concerned that ERO-Net dash board shall be visited and verified regularly. Any lapse on part of the concerned officer shall expose him/her to disciplinary actions.

16.Observation:- In addition to Divisional Commissioners, who shall act as Electoral Roll Observers for districts comprised within their Divisions, the Commission may depute its observers/CEOs officers/roll auditors to randomly check/audit and supervise the revision process. Hence, all

(3)

absolutely essential that all roll related records including reports of progress as well as lists of the locations where field operations are in progress, should be kept up to date and made available to the observers.

17. Meeting with Political Parties and sharing of electoral rolls: (i) All DEOs and CEO shall separately call meetings of political parties and explain the schedule and seek cooperation expected of them before the date of draft publication. The draft publication should be done on the approved date with due fanfare publicity and the copies of draft rolls should be handed over to recognized political parties in public meeting in the presence of press and media. In any case, proper acknowledgement receipts from the representatives of political parties must be obtained and kept in record.

(ii) The CEO should write to all recognized national and state level political parties informing them the important points of the law and procedures of the revision and seek their cooperation in the roll revision exercise. A copy of letter issued to them may be endorsed to the Commission for record.

(iii) List of claims and objections should also be made available by ERO to all political parties on weekly basis.

(iv) Two copies of complete set of draft Electoral Rolls and Final Electoral Rolls immediately after draft and final publication respectively shall be supplied free of cost to recognized political parties in accordance with the provisions of rule 11(c) and 22 (c) of Registration of Electors Rules, 1960. (Please refer to para 25.3 of Chapter 25 of Manual on Electoral Rolls, 2016 for detailed guidelines in the matter.

(v) CEO will request to the recognized political parties to identify and appoint Booth Level Agent (BLA) for each polling station who would be associated with BLO during revision period. The BLOs will go through the draft electoral roll with BLAs of recognized political parties of State concerned and identify the corrections, etc. It is pertinent to mention that BLAs once appointed from a recognized political party will continue as BLA, unless their appointment is rescinded /revoked by the political party concerned.

(vi) With a view to ensure more involvement of political parties, the Commission has allowed BLAs of a recognized political parties to file applications in bulk, subject to the condition that a BLA shall not submit more than 10 Forms to BLO at one time/in one day. If a BLA files more than 10 Applications/Forms during entire period of filing claims and objections, then the cross verification must be done by ERO/AERO themselves. Further, the BLA will also submit a list of application forms with a declaration that he has personally verified the particulars of the application forms and is satisfied that they are correct.

18. Transparency Measures: In order to facilitate the stakeholders and bringing more transparency in the process of electoral registration, the practice of computerization and posting of all application forms received in Forms 6, 6A, 7, 8 and 8A on the website of the CEO on a day to day basis, shall continue, in addition to putting draft electoral roll, final electoral roll, list of claims and objections on CEOs' website and sharing of the same with recognized political parties. The CEO shall extract a report on status of disposal of claims and objections received during the revision from ERO-Net and put the same on his website on weekly basis for information of general public/citizens.

19. Publicity: - Adequate publicity and awareness drive shall be ensured by DEOs and CEO regarding the summary revision programme. All the DEOs and CEO shall get the revision schedule properly disseminated to media, political parties and social organizations/RWAs and reach out to electors/eligible population extensively well before the date of draft publication of electoral rolls. For making the purpose of publication of draft rolls effective, series of SVIEP events, multiple and periodic meetings with political parties at Taluk, district and state levels and regular press meets may be organized.

20. The Commission's approval for Final Publication:- The CEO shall take prior written clearance of the Commission for final publication of the electoral rolls. A request to that effect shall be made to the Commission by the Chief Electoral Officer along with Formats 1-8 by 20th December, 2018 and with Formats 1-8 and memoranda/note mandatorily, explaining as to how the roll revision process has achieved the targets fixed and suggesting the strategy to address shortfalls, if any, during next continuous updation. This should, in any case, be done at least 7 days before the date of final publication, so that clearance of the Commission may be conveyed at least 3 days before the date of final publication.

21. Preparation of EPIC for newly registered young electors: Preparation of Elector Photo Identity Card (EPIC) for the first time young electors may be done latest by 20th January 2019 and handed over to BLO/ERO/DFO etc by 22nd January 2019 for ceremonial distribution on 25th January 2019, the National Voters' Day.

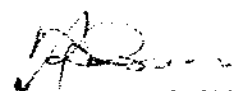
22. It may further be noted that all communications and clarification relating to the revision should be addressed to the Pr Secretary/Secretary (in charge of the State/UT) in the Commission who will not only reply to the CEO concerned without any delay but also ensure that there is no slippage in the roll revision programme of the States under their charge. They will closely monitor the pre-revision activities and roll revision programme of their respective States/UTs therefore, the CEOs must forward requisite report on progress of revision process at regular interval.

23. The CEOs and all officers are further requested to extensively use the e-mail facility for prompt and accurate exchange of communication.

24. A copy of this letter should also be circulated among all DEOs/EROs in the State for taking immediate appropriate necessary action.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,


(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

- (iv) जिला निर्वाचन अधिकारी को अपेक्षित संख्या में प्रतियां यथास्थिति, अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस आयुक्त को भी देनी चाहिए। प्रतियां संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (रों) को दी जानी होती हैं। एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- (v) मतदान केंद्रों की सूची प्रारूप प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन के सभी चरणों में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक शासकीय वेबसाइट पर भी डाली जानी चाहिए।

अध्याय-4

विद्यमान मतदान केन्द्रों की सूची में यौक्तिकरण/परिवर्तन

4.1 मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण क्या है?

निर्वाचन आयोग ने अनुदेश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 निर्वाचकों और शहरी क्षेत्रों में 1400 निर्वाचकों के लिए एक मतदान केन्द्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस समय, देश में 9,40,469 मतदान केन्द्र हैं, तथापि, निर्वाचक मंडल में नियमित वृद्धि होने से, यह संख्या निश्चित बढ़ेगी। निर्वाचकों की सदैव बढ़ती संख्या और विभिन्न अन्य घटनाक्रमों यथा विद्यमान भवनों की स्थिति में गिरावट, परिक्षेत्र में समुचित नए भवनों की उपलब्धता, मतदान केन्द्रों में बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं, की स्थिति भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन, विधि एवं व्यवस्था स्थिति में परिवर्तन आदि के मद्देनजर, विद्यमान मतदान केन्द्रों की समय-समय पर पुनरीक्षा किया जाना अपेक्षित है। यह कार्य मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण कहलाता है।

4.2 सहायक मतदान केन्द्र

(i) सहायक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने के कारण-

मतदान केन्द्र का यौक्तिकीकरण साधारणतया निर्वाचक नामावलियों के प्रत्येक पुनरीक्षण से पहले किया जाता है। किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान, यौक्तिकीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाता है किंतु कभी-कभी निम्नलिखित कारणों से, विद्यमान (मूल) मतदान केन्द्र को दो भागों/तीन भागों में बांटकर सहायक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जानी होती है:-

- (क) यदि निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद, यह ध्यान में आता है कि मतदान क्षेत्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या विहित सीमा से अधिक है और विद्यमान मतदान केन्द्र में निर्वाचकों का प्रबंधन करना संभव नहीं है।
- (ख) यदि निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक किसी निर्वाचन/उप निर्वाचन की उदघोषणा की जाती है और जिला निर्वाचन अधिकारी के पास मतदान केन्द्र के यौक्तिकीकरण के लिए समय नहीं होता तथा निर्वाचन को विद्यमान निर्वाचक नामावली के आधार पर संचालित किया जाना अपेक्षित होता है।

(ii) ऐसी शर्तें जिनके अधीन सहायक मतदान केन्द्रों की अनुमति दी जाती है:-

- (क) सहायक मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या वहीं होगी जो मूल मतदान केन्द्र की है किंतु उसके बाद "क", "ख" आदि जोड़ा जाएगा।
- (ख) यथा व्यवहार्य सहायक मतदान केन्द्र मूल मतदान केन्द्र वाले भवन या परिसरों में ही अवस्थित होंगे।
- (ग) सहायक मतदान केन्द्र को पृथक भवन में केवल तभी अवस्थित किया जा सकता है जब अपरिहार्य कारण से समुचित कक्ष उपलब्ध न हो। किंतु यह मूल मतदान केन्द्र वाले क्षेत्र के भीतर ही होगा।
- (घ) सहायक मतदान केन्द्र को पृथक क्रम संख्या नहीं दी जाएगी चाहे वह पृथक भवन में अवस्थित हो। इसकी क्रम संख्या वहीं होगी जो मूल मतदान केन्द्र की है। किंतु इसके बाद "क" या "ख" होगा क्योंकि मूल मतदान केन्द्र और इसके सहायक मतदान केन्द्र में निर्वाचक नियमावली के एक ही भाग में दर्शाए गए निर्वाचक हो सकते हैं।

4.3 मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण, निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से पहले किया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निर्वाचनों से काफी पहले मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण करना बेहतर होता है ताकि सभी हितधारियों से समुचित रूप से परामर्श किया जा सके और यौक्तिकीकरण के विश्लेषण से पहले सभी मतदान केन्द्रों का वास्तविक रूप से सत्यापन किया जा सके। किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान यौक्तिकीकरण का कार्य निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण से पहले पुनरीक्षण पूर्व क्रियाकलाप के रूप में किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर इस विषय पर अनुदेश जारी किए हैं। मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया गया है:-

4.3.1 वास्तविक सत्यापन

- (i) मतदान केन्द्र अवस्थानों तथा निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भागों के शत-प्रतिशत वास्तविक सत्यापन के बाद ही यौक्तिकीकरण किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामोद्दिष्ट कोई वरिष्ठ अधिकारी वास्तविक सत्यापन का कार्य करेगा। तथापि, मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण कार्य की समग्र जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी। एकरूपता के प्रयोजनार्थ, जिला निर्वाचन अधिकारी एक प्रपत्र तैयार कर सकेगा जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित मानदंडों तथा ऐसे अतिरिक्त बिंदुओं, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी उपयुक्त समझे को कवर किया जाना चाहिए। मतदान केन्द्रों के सत्यापन और यौक्तिकीकरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारी/नामोद्दिष्ट सत्यापन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के वास्तविक सत्यापन के बाद प्रपत्र पर तारीख सहित हस्ताक्षर करना चाहिए।
- (ii) पहाड़ियों, वनों, नदियों, जंगलों आदि जैसे अवरोधों की विद्यमानता पर सम्यक ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी मतदान केन्द्र में किसी बड़ी नदी के दोनों ओर के गांव शामिल नहीं होने चाहिए; किंतु जहां गांव ही किसी नदी या धारा द्वारा विभाजित हो तो इसे जब तक कि विशेष कारण न हों, मतदान प्रयोजनों के लिए खंडित नहीं किया जाना चाहिए।
- (iii) शत-प्रतिशत वास्तविक सत्यापन करते समय, सभी मौजूदा मतदान केन्द्रों का निम्नलिखित का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए-
- क्या मतदान केन्द्र क्षेत्र का विद्यमान मतदान केन्द्र सूची में सही-सही एवं पूरी तरह से वर्णन किया गया है।
 - क्या मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित हैं;
 - क्या मतदाताओं को मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए नदियों/नहरों/घाटियों को पार करना होगा;
 - क्या मतदाताओं से मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए 2 किमी. से अधिक की दूरी तय किया जाना अपेक्षित है;
 - क्या मतदान केन्द्र अवस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से अधिक मतदान केन्द्र तथा शहरी क्षेत्रों में 4 से अधिक मतदान केन्द्र हैं;
 - क्या भवन जर्जर या खतरनाक है;
 - क्या मतदान केन्द्र कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर है और क्या इसके दो दरवाजे हैं;
 - क्या मतदान केन्द्र पहली मंजिल या इससे ऊपर है;

- क्या मतदान केन्द्र प्राइवेट भवन में है;
- क्या मतदान केन्द्र किसी पुलिस थाना/अस्पताल/धर्मशाला/मंदिर या किसी धार्मिक स्थान में अवस्थित है;
- क्या किसी राजनैतिक दल का कार्यालय मतदान केन्द्र अवस्थान से 200 मीटर के भीतर स्थित है;
- क्या भवन में बिजली का कनेक्शन है;
- क्या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए रैम्प की व्यवस्था की गई है;
- क्या मतदान केन्द्र परिसरों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधाएं विद्यमान हैं;
- क्या मतदाताओं को धूप एवं वर्षा से बचाने के लिए शेड है;
- क्या मतदान केन्द्र में दूरभाष कनेक्शन है। यदि हां, तो दूरभाष नम्बर क्या है;
- क्या अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति/जनजाति की बहुलता वाले परिक्षेत्रों में मतदान केन्द्र ऐसी रीति में अवस्थित हैं कि ऐसे समुदायों को मतदान केन्द्र पहुंचने एवं अपने मत डालने से रोका जाता है।

4.3.2 यौक्तिकीकरण के दौरान किसी नए मतदान केन्द्र की स्थापना हेतु मानदंड

मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण के दौरान वास्तविक सत्यापन के बाद नए मतदान केन्द्र के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

- किसी मतदान केन्द्र को निर्दिष्ट किए जा सकने वाले निर्वाचकों की अधिकतम संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में 1200 एवं शहरी क्षेत्रों की दशा में 1400 है। तथापि, विभिन्न मुद्दों के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवश्यक औचित्य प्रदान करके उनके द्वारा प्रस्तावित निम्नतर या उच्चतर सीमा को अनुमोदित करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुरोध कर सकते हैं।
- निर्वाचक भाग को विभाजित करके सभी विद्यमान सहायक मतदान केन्द्रों को मुख्य मतदान केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- नए मतदान केन्द्र का प्रस्ताव किया जा सकेगा यदि किसी गांव में 300 से अधिक निर्वाचक हैं तथा मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध है।
- यदि कई निवास यूनिटों के साथ कोई नई कॉलोनी अस्तित्व में आई है तो नया मतदान केन्द्र सृजित किया जा सकेगा।
- किसी मतदान केन्द्र को निर्दिष्ट मतदान क्षेत्र सघन होना चाहिए।
- अल्पसंख्यकों/समाज के कमजोर वर्गों यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले परिक्षेत्रों में नया/पृथक मतदान केन्द्र सृजित किया जा सकेगा चाहे निर्वाचकों की संख्या कितनी भी हो। नोडल अधिकारी को ऐसे लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी संगठनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई एक लिखित रिपोर्ट देनी चाहिए।

- संपूर्ण कार्य सांविधिक उपबंधों तथा निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के आलोक में भय या पक्ष के बिना पेशेवर रीति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना होगा।
- इस रीति में मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण के बाद, मतदान केन्द्रों के अवस्थान में अंतिम क्षण में परिवर्तन आवश्यक नहीं होने चाहिए।
- माओवादी या आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव करते समय निर्वाचन संचालित करने के लिए भेजे गए मतदान दलों एवं पुलिस बल की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र ऐसे स्थानों में बनाए जाने चाहिए जहां तक आसान एवं सुरक्षित, पहुंच हो। यदि उपलब्ध बल का अधिकतम एवं तालमेल युक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मतदान केन्द्र ऐसे क्षेत्रों में समूह (क्लस्टर) में प्रदान किए जाते हैं तो यह उपयोगी होगा।

4.3.3 राजनैतिक दलों के साथ परामर्श

विद्यमान मतदान केन्द्रों के वास्तविक सत्यापन के बाद तैयार किए गए प्रस्तावों पर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इस संबंध में, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों के साथ परामर्श और मतदान केन्द्रों की सूची की तैयारी एवं प्रकाशन के संबंध में जारी सभी अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों एवं सुझावों की सम्यक रूप से जांच की जानी चाहिए और निस्तारण के बाद उन्हें समुचित उत्तर दिया जाना चाहिए।

4.3.4 कंट्रोल टेबल अद्यतन

“भारत निर्वाचन आयोग कंट्रोल टेबल्स डाटाबेस” में मतदान केन्द्र टेबलों को यौक्तिकीकरण किए गए मतदान केन्द्रों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजने से पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाना चाहिए। “ई सी आई कंट्रोल टेबल्स डाटाबेस” से मतदान केन्द्रों की सूची के प्रिंटआउट को प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

4.3.5 अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजना

मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण के अनुमोदनार्थ निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना चाहिए:-

- (i) मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण में पालन की गई प्रक्रिया के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट में राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी प्रस्तावों तथा क्या प्रस्ताव स्वीकृत किए गए या नहीं, इसके ब्योरे का भी उल्लेख होना चाहिए। यदि राजनैतिक दलों

- के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जाते हैं तो रिपोर्ट में उन्हें स्वीकृत नहीं किए जाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव में राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक, जिसमें मतदान केन्द्र के यौक्तिकीकरण के विषय पर चर्चा की गई थी, के कार्यवृत्त की प्रतियां होनी चाहिए। प्रस्ताव में यह विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि राजनैतिक दलों के किन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया है, साथ में कारण भी होने चाहिए।
- (ii) रिपोर्ट में इस बारे में एक विशेष खंड होना चाहिए कि किस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है कि समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों की डराने-धमकाने के बिना मतदान केन्द्रों तक निर्बाध पहुंच है।
- (iii) प्रस्ताव में यह विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि कोई भी मतदान केन्द्र जर्जर भवन या धार्मिक स्थल या किसी राजनैतिक दल के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर अवस्थित नहीं है।
- (iv) प्रस्ताव में यह विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि सभी आधारभूत सुविधाएं अर्थात् रैम्प, पेयजल, शौचालय, शेड एवं आश्रय आदि की व्यवस्था प्रस्तावित मतदान केन्द्रों में की गई है।

4.4 निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बाद मतदान केन्द्र के अवस्थान में परिवर्तन

- (i) निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी मतदान केन्द्र को आबंटित मतदान क्षेत्र के भीतर मतदाताओं की संख्या में अंतर के फलस्वरूप हुए प्रत्येक परिवर्तन की रिपोर्ट आयोग को सूचनार्थ दी जानी चाहिए।
- (ii) कभी कभी, अंतिम क्षणों में निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के पश्चात मतदान केन्द्रों के अवस्थान को बदलकर नए भवनों या स्कूलों में ले जाना आवश्यक हो सकता है, जहां मतदान केन्द्र के लिए मूल रूप से प्रस्तावित भवन या स्थल के मालिक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी बन गया हो या किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के लिए काफी सहानुभूति रखता हो या भवन किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो गया हो। ऐसे सभी परिवर्तनों की सूचना अनुमोदन हेतु तत्काल आयोग को दी जानी चाहिए। सूचियों के अनुमोदन के बाद, मतदान केन्द्रों को एक गांव से दूसरे गांव में या एक स्थल से दूसरे स्थल में स्थानांतरित करने के लिए राजनैतिक दलों एवं व्यक्ति विशेष के अनुरोधों पर केवल आपवादिक मामलों में ही विचार किया जाना चाहिए, जहाँ प्रस्तावित परिवर्तन के पीछे सार्वजनिक सुविधा की महत्ता सर्वोपरि हो। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाने पर उन्हें अन्य राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों से परामर्श करना चाहिए और तब ही इस मामले में अपनी सिफारिशें आयोग को देनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी को किसी भी स्थिति में निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र के अवस्थान में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्वाचन को अमान्य घोषित किया जा सकता है। जहां परिवर्तन अपरिहार्य हो जाते हैं और करने पड़ते हैं वहां ऐसे परिवर्तनों को पूर्व अनुमोदन के लिए आयोग को भेजा जाना चाहिए। परिवर्तनों का पूरा प्रचार किया जाना चाहिए तथा निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों आदि को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।

4.5 किसी मतदान केन्द्र के भवन के नाम में परिवर्तन

किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की सूची के अनुमोदन के बाद यदि भवन, जिसमें मतदान केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, के नामकरण में कोई परिवर्तन होता है, उदाहरण के लिए, प्राथमिक विद्यालय का मध्य विद्यालय में स्तरोन्नयन इत्यादि। किंतु मतदान केंद्र के अवस्थान में अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे परिवर्तन के मामलों को आयोग के पूर्वानुमोदन के लिए आयोग को संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, आयोग को ऐसे परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए। ऐसे परिवर्तन के बारे में राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों आदि को भी लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।

4.6 भावी साधारण/उप निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की सूची की तैयारी

जब कभी भविष्य में उस निर्वाचन क्षेत्र में कोई साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन आयोजित किया जाना हो, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उस निर्वाचन के बाद निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के कारण पहले ही अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची में कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक है। यदि किसी ऐसे निर्वाचन में, अनुमोदित सूची में परिवर्तन या रूपांतरण आवश्यक नहीं समझा जाता है और इसे उस निर्वाचन के लिए संपूर्ण रूप में अपनाए जाने का प्रस्ताव है, तो उस सूची के संबंध में आयोग का आगे कोई और अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा तथा ऐसी सूची को निर्वाचन से पहले आयोग से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे आयोग को भेजने की जरूरत नहीं होगी। तथापि, निर्वाचन आयोग को अभ्यर्थिता की वापसी की अंतिम तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व इस तथ्य की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। तथापि, जहां, आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची को उक्त निर्वाचन के लिए रूपांतरणों के साथ अपनाए जाने का प्रस्ताव है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की स्थानीय शाखाओं के प्रतिनिधियों तथा विधायकों की बैठक बुलानी चाहिए और परामर्श के बाद एक नया समेकित प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजना चाहिए।

अध्याय 5

अतिसंवेदनशीलता मैपिंग और संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिह्नित किया जाना

5.1 कमजोर वर्गों के क्षेत्रों की अतिसंवेदनशीलता मैपिंग